कृपया प्रकाशनार्थ **13 जुलाई 2013**

राष्ट्र का पहला महिला विश्वविद्यालय - एसएनडीटी को केंद्र सरकार भूल गयी ? - राम नाईक

मुंबई, शनिवार : ''राष्ट्र का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई का ख्यातकीर्त एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार बेदखल क्यों कर रही है?'' ऐसा सवाल भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री.राम नाईक ने उठाया है. ''स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से रायबरेली में महिला विश्वविद्यालय शुरु करने का केंद्रिय मंत्री परिषद का 11 जुलाई का निर्णय मात्र वर्ष 2014 के चुनाव से प्रेरित है. यह निर्णय केवल मतदाताओं की चापलुसी करनेवाला नही तो शिक्षा क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का स्वयं सरकार को ही ज्ञान नही यह स्पष्ट करनेवाला है'', ऐसी कडी आलोचना भी श्री.राम नाईक ने आज मुंबई में जारी प्रेस विज्ञप्ति में की है.

अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए श्री.राम नाईक ने आगे कहा, ''2014 के लोकसभा चुनाव अब नजदिक आ रहे है. ऐसे में काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में रु.500 करोड की लागत से 'पहला' महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का ऐलान केवल चुनावी स्वार्थ के लिए किया गया है, यह तो स्पष्ट है. साथ ही साथ केंद्रिय मंत्री परिषद ने इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय को देश का 'पहला' महिला विश्वविद्यालय कह कर चापलुसी और अज्ञान की हद पार कर दी. भारतरत्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में 'दी इंडियन वुमेन्स युनिव्हर्सिटी' के नाम से पहला महिला विश्वविद्यालय प्रारंभ किया. स्वतंत्रता के बाद 1951 में उसका 'श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) वुमेन्स युनिव्हर्सिटी ' ऐसा नामांतरण किया गया, साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक संविधानिक प्रावधान भी किया गया. पुरे विश्व में मशहूर इस विश्वविद्यालय का 1939 का दिक्षांत समारोह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, तो वर्ष 1941 में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का रौप्य महोत्सव संपन्न हुआ. वर्ष 1958 में प्रधानमंत्री श्री. पंडित नेहरु के हातों विश्वविद्यालय के संस्थापक महर्षि धोंडो केशव कर्वे को भारतरत्न से सम्मानित किया गया, तो स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में विद्यापीठ का सुवर्ण महोत्सव 1966 में मनाया गया. दूरसंचार मंत्री डा. शंकर दयाल शर्मा के करकमलोंद्वारा 1976 में विश्वविद्यालय के हीरक महोत्सव के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया, तो 1991 में अमृत महोत्सव भी हर्षोल्हास में संपन्न हुआ.'' अब तीन वर्ष बाद इस विश्वविद्यालय को सौ साल पुरे होंगे, केवल भारत में ही नहीं तो विश्व में इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है. फिर भी इसके बारे में युनिव्हर्सिटी ग्रँटस् कमिशन के अध्यक्ष रह चुके प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह अनभिज्ञ है ऐसा कैसे माने? महाराष्ट्र के दो अग्रणी नेता कृषिमंत्री श्री.शरद पवार और गृह मंत्री श्री. सुशीलकुमार शिंदे मंत्री परिषद की सभा में ध्यान नहीं दे रहे थे यां फिर दिल्ली की हवा में महाराष्ट्र की शिक्षा परंपरा को वें भूल चूंके है क्या ऐसा सवाल भी श्री. राम नाईक ने किया.

''जिस एसएनडीटी विश्वविद्यालय ने देश में स्त्री शिक्षा की अगुवाई की, महिलाओं के सबलीकरण का प्रारंभ करने में अहम् भूमिका निभायी, उसी विश्वविद्यालय को कांग्रेस सरकार भूल गयी, इसकी हम कडी निंदा करते है. प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय को शिक्षा क्षेत्र में जिन्होने विशेष कार्य किया है ऐसी श्रीमती सावित्रीबाई फुले, भगिनी निवेदिता, डा. आनंदीबाई जोशी, श्रीमती रमाबाई रानडे जैसी किसी विदुषी का नाम देना अधिक योग्य रहेगा,'' ऐसा भी श्री. नाईक ने कहा. इस पुरे मामले की आलोचना करनेवाला पत्र मैंने प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को भेजा है ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अंत में कहा.

(कार्यालय मंत्री)

संलग्न: मंत्री परिषद की प्रेस विज्ञप्ति

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
मंत्रिमंडल

11-जुलाई-2013 15:18 IST

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय होगा। विशेषकर महिलाओं के लिए स्थापित किए जाने वाला यह इस तरह का देश में पहला विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित होगा।

एक विधेयक जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक-2013 होगा, इसे संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना में 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस विश्वविद्यालय के जरिए बेहतर रोजगारोन्मुख आधारभूत पाठ्यक्रम और अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराकर देश में महिलाओं के सर्वांगिण विकास के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

देश की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में से 58.6 करोड़ महिलाएं हैं जिनमें से 9.5 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं।

***

नीणा/आनन्द/शदीद-4064